शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 5 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 27 – 3 फरवरी 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या कांग्रेस में एक बड़ा विद्रोह और विरोध मुखर होने जा रहा है?

- दो दर्जन विधायकों के हस्ताक्षरों से उठी चर्चा
- 1990 की तर्ज पर प्रदेश में बड़े कर्मचारी आन्दोलन की संभावना

शिमला/शैल। क्या हिमाचल कांग्रेस में एक बड़े विद्रोह और विरोध की परिस्थितियां बनने लग पड़ी है? क्या परिस्थितियां हिमाचल सरकार के लिये घातक होगी? यह सवाल और ऐसे ही कई और सवाल इस प्रदेश की राजनीतिक तथा प्रशासनिक गलियारों में चर्चा में आने लगे हैं। क्योंकि हिमाचल सरकार वित्तीय कुप्रबंधन के लिये जितना पूर्व सरकार को दोषी करार देती आ रही है उससे कहीं ज्यादा इस कुप्रबंधन के प्रमाण अपने खिलाफ खड़े करती जा रही है। विपक्ष एक लम्बे अरसे से यह आरोप लगाता आ रहा है कि यह सरकार केन्द्रीय योजनाओं के नाम पर मिल रहे पैसे को डाईवर्ट करके अपने खर्च चलाने के लिये इस्तेमाल कर रही है। इसका प्रमाण उस समय सामने आ गया जब भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने यह आरोप लगा दिया की समग्र शिक्षा अभियान के पैसे से एलिमेंट्री शिक्षकों का वेतन अदा किया गया। रणधीर शर्मा ने इस आरोप की पुष्टि में सरकार द्वारा 20 जनवरी को लिखा गया पत्र भी सामने रखा। ऐसे ही आरोप वन और अन्य विभागों को लेकर सामने आये हैं। इन्हीं आरोपों के विधानसभा सचिवालय द्वारा की गई नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इन नियुक्तियों के लिये अपनायी गयी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। इसी के साथ युक्तिकरण के नाम पर बिजली बोर्ड में 700 पदों को समाप्त करने और आउटसोर्स पर रखे गये 81 ड्राइवरों को निकाले जाने के प्रकरण ने जलती आग में घी डालने का काम किया है। आउटसोर्स के माध्यम से की जाने वाली भर्तीयों को संविधान के अनुच्छेद 16 की उल्लंघना करार देते हुये इन पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद कुछ कंपनियां सरकारी विभागों के नाम पर युवाओं से आवेदन मांगने का काम जारी रखे हुये हैं क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। इस तरह कर्मचारियों में 1990 की तर्ज पर एक बड़े आन्दोलन की स्थितियां बनती जा रही हैं।

दूसरी ओर सरकार वित्तीय संकट से निपटने के लिये आम आदमी पर और ज्यादा करों और शुल्कों का बोझ डालने के विकल्प पर चल रही है। कर्ज की सीमा पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसी वित्तीय परिदृश्य में विपक्ष ने बजट पूर्व होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार कर दिया है। विधायकों और बड़े अधिकारियों को पूरी तरह यह जानकारी है कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में सरकार की कोई भी घोषणा जमीन पर उतरना संभव नहीं है। जब राजनीतिक क्लास के सामने यह आ जाता है कि सरकार विकास के किसी भी काम को अमली जामा पहनाने की स्थिति में नहीं रह गयी है तब सरकार की करनी और कथनी की व्यवहारिक विवेचना शुरू हो जाती है। इस प्रकार का कार्य सूत्र अब तक व्यवस्था परिवर्तन रहा है जो अब सूत्र से निकलकर जुमले के दायरे में आ गया है। स्वभाविक है कि जो सरकार शिक्षकों का वेतन देने के लिये समग्र शिक्षा के धन का इस्तेमाल करने पर विवश हो जाये वह राजीव गांधी डे – बोर्डिंग स्कूल बनाने और बच्चों को विदेश भ्रमण पर ले जाने का प्रबंध कैसे करेगी? यह सवाल अब आम आदमी भी पूछने लगा पड़ा है।

अब कांग्रेस के विधायकों का एक बड़ा वर्ग सरकार से हटकर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंता और चिंतन करने लगा पड़ा है। चर्चा है कि कांगड़ा के एक विधायक के घर में हुई बैठक में इस पर खुलकर चर्चा हुई है। बैठक में यह प्रश्न उठा है कि विधानसभा का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया था और उसके बाद नेतृत्व का चयन उच्च कमान ने स्वयं किया था। यह एक स्थापित सच है कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस जैसी पार्टी में संगठन पृष्ठभूमि में चला जाता है और अग्रणी भूमिका में केवल सरकार रह जाती है। इसी अग्रणी भूमिका के कारण सरकार बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के स्थान पर पहले मित्रों को ताजपोशियां दी गयी और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गयी। इस अनदेखी की शिकायत हाईकमान तक भी पहुंची। जब हाईकमान ने भी इस सब

शेष पृष्ठ 8 पर.....

कांग्रेस के विधायकों ने कहा हमारी स्थिति भी विपक्ष जैसी:जयराम

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कांग्रेस सरकार के नकारात्मक रवैये एवं विधायकों के अपमान को लेकर 3 और 4 फरवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठक का भाजपा बहिष्कार करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और दो वर्षों से जो हमारे चुने हुए अपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है।

उन्होंने कहा अगर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कहना चाहेंगे तो एक दो स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के जो हमने प्राथमिकता पीडब्लूडी और आईपीएच में दी है उसकी डीपीआर

बनाने की प्रोसेस दो वर्ष के कांग्रेस कार्यकाल में भी शुरू नहीं हुई है। यह तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है , सवाल यह उठता है कि जब आपको डीपीआर ही नहीं बनानी है तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर विधायकों के कहने पर काम कैसे होंगे? आज हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू कर दी गई है कि पिछली डीपीआर जो बन कर के तैयार हो भी गई है उसमें भी लिस्ट बनाकर के मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जा रही है, कौन सी डीपीआर नाबार्ड के सामने पेश करनी है और उसमें फिर जो विपक्ष के विधायकों की डीपीआर बनी है उनके सामने काटा जाये। जयराम ने कहा कि कांग्रेस के भी उन विधायकों के लिए प्राथमिकता तय हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीब और नजदीक है। केवल उनकी स्कीमों के सामने टिक लगता है और जब हमने पिछले कल बहिष्कार का फैसला किया

शेष पृष्ठ 8 पर.....

नशे के खिलाफ राज्यपाल ने चायल में चलाया नशामुक्ति अभियान

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल के प्रथम नागरिक होने के नाते राज्य में बढ़ते नशे को लेकर वह चिंतित हैं। उनका प्रयास है कि हर घर नशे से

सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि अगर हर घर सुरक्षित होगा तो प्रदेश भी सुरक्षित रहेगा।

राज्यपाल सोलन जिले के पर्यटक स्थल चायल में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि नशा घर-घर तक पहुंच रहा है और चिट्टा जैसे नशे से युवाओं की मौत हो रही है। बढ़ते हुए नशे को कैसे रोके, इसपर विचार करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है हमें इसे ''नशा भूमि'' नहीं बनने देना है। उन्होंने नशा मुक्ति के अभियान में सोलन और शिमला पुलिस के प्रयासों की सराहना की और पुलिस अधीक्षकों की पीठ भी थपथपाई।

राज्यपाल ने कहा कि राजभवन से उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के लिये जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद, सोलन जिले में ही तीन कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि आज हमें 'डिमांड' को ही खत्म करना है और नशे के आदि व्यक्ति का उपचार सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कुछ निजी स्तर पर चलाये जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशामुक्ति अभियान को उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के उनके कार्यकाल के बाद प्रदेश में उन्हें उम्मीद जगी है। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे नशामुक्ति के इस अभियान में सबसे अधिक कार्य कर सकती हैं और नशामुक्त वातावरण बनाने में सहयोग कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि नशे के कारण आज सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए वे 'नशा न लेने का शपथ पत्र' भरेंगे और यदि वे नशा करते पाये गये तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

इस अवसर पर, मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित नशा निवारण बोर्ड के पूर्व संयोजक ओ.पी. शर्मा ने कहा कि कुछ युवाओं द्वारा नशा लेने के पीछे का कारण यह है कि हमारी भागीदारी उनके प्रति नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। सोच में परिवर्तन नहीं होगा तो सूचना उपलब्ध नहीं होगी जिसके कारण समस्या और गंभीर हो जायेगी। उन्होंने कहा कि कानून कार्यान्वयन एजेंसियों पर हम पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते इसके लिए सामाजिक चेतना जरूरी है।

महर्षि मारकण्डेश्वर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य प्रो. रवि शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि चिट्टे के कारण अधिकांश मौते हो रही हैं। विभिन्न संगठनों और जिम्मेदार नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि वे युवाओं को इस दिशा में जाने से बचाएं। नशे के कारणों और पहचान के बारे में जानकारी दें। नशा करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव और अन्य लक्षणों को पहचानें।

परवाणु की पुलिस अधीक्षक मेहर पंवर ने कहा कि सिनथैटिक ड्रग्स आज सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस आपूर्ति और मांग, दोनों ही तरफ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 से आज दिन तक सोलन पुलिस ने 139 मुकद्में दर्ज किए और 321 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। और बड़े स्तर पर नशे की खेप को पकड़ा है।

ग्राम पंचायत की प्रधान ऊषा शर्मा ने पंचायत की ओर से नशामुक्ति अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया।

चायल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष देविंदर वर्मा ने आश्वासन दिया कि एसोसिएशन भी उनके नशामुक्ति अभियान में शामिल होगा।

राज्यपाल ने जीप क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक विंटर स्पीति एक्सपीडिशन 2025 का शुभारम्भ किया, जिसका थीम था – एन्टी ड्रग रैली। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन प्राकृतिक सुन्दरता को प्रदर्शित करने का एक उत्तम प्रयास है, बल्कि यह प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अनुकरणीय उदाहरण भी है। उन्होंने कहा कि यह रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम निश्चय ही हमारे समाज को नशा मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देगा। उन्होंने जीप क्लब और होटल एसोसिएशन चायल को इस पहल के लिए बधाई दी।

संत संस्कृति के स्तम्भः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि संत भारत की महान संस्कृति के स्तम्भ और ज्ञान

का प्रकाश पुंज होते हैं। उन्होंने कहा कि वे हमारा सही दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हैं और मानवता के उच्च मूल्यों को आत्मसात कर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। राज्यपाल ने आज नोएडा में परम पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज की दिव्य रामकथा में यह बात कही।

उन्होंने एन. शर्मा और सुप्रिया शर्मा को कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से सकारात्मक वातावरण बनने के साथ-साथ श्रोताओं को दिव्य ऊर्जा मिलेगी और उनमें अनुशासन, सत्य, भक्ति, कर्त्तव्य और त्याग के उच्चतम मूल्य पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ये मूल्य जीवन में सफलता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर नोएडा के संसद डॉ. महेश शर्मा और नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. लोकेश तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में सोलन जिला के विधायकों के साथ

बैठक की और जिला से संबंधित विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी और फीडबैक ली। उन्होंने कहा कि जिला में निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए जन-प्रतिनिधियों को निरंतर प्रयास करने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से जिला की भावी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि नवीन परियोजनाओं में नवाचार को विशेष अधिमान दिया जाना चाहिए और उनकी परिकल्पना 'हरित राज्य' दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण व राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए विधायकों से निरंतर सार्थक प्रयास करने को कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन योजनाएं व कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों को फलीभूत करने के लिए लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सोलन जिला का प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में अहम योगदान है। प्रदेश सरकार सोलन जिला का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में विधायक राम कुमार चौधरी, संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी और हरदीप सिंह बावा उपस्थित थे।

क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए समिति गठित

शिमला/शैल। क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की है। यह समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में गठित की गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि यह समिति मौजूदा अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों का आकलन करेगी ताकि प्रदेश के लिए क्षेत्र विशेष कार्बन बाजार विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन में राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से संभावित कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान का कार्य भी करेगी। इसके अलावा, यह कार्बन क्रेडिट के लिए राज्य जलवायु नीति और संबंधित ढांचे को तैयार करने में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि विभागों को कार्बन क्रेडिट सुरक्षित करने के लिए परियोजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ समिति द्वारा परियोजना डेवलपर्स, सलाहकारों, खरीदारों व व्यापारियों आदि को परियोजनाएं विकसित करने में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा यह भारतीय कार्बन बाजार और अन्तरराष्ट्रीय कार्बन मानकों के प्रशासकों के साथ निरंतर संवाद भी सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति राज्य के कार्बन क्रेडिट्स के लाभों को अधिकतम करने के लिए नई और मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को पुनः संगठित करने के लिए सिफारिशें भी देगी। यह भारत और अन्य राज्यों द्वारा लागू की गई प्रथाओं और सफल परियोजनाओं का अध्ययन कर उनकी रणनीतियों का भी विश्लेषण करेगी।

भाजपा नेताओं ने पूर्व सांसद किशन कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा डॉ. राजीव बिन्दल, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश सह-प्रभारी संजय टण्डन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर सिंह, सुरेश चंदेल, सुरेश भारद्वाज, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश कश्यप, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, डॉ. सिकंदर कुमार, हर्ष महाजन, लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर, डॉ. राजीव भारद्वाज, कंगना रणौत, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं विधायक विपिन परमार, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं विधायक विक्रम ठाकुर, मण्डी संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गोविन्द ठाकुर, शिमला संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं विधायक सुखराम चौधरी, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल शर्मा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद किशन कपूर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, वे 73 वर्ष के थे और पिछले काफी समय से बीमार थे, उन्होनें पीजीआई चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली।

भाजपा नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संत्पत परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री किशन कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मंत्री किशन कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका निधन पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ। वह 73 वर्ष के थे।

राज्यपाल ने कहा कि किशन कपूर जन समर्पित नेता थे और उन्होंने प्रदेश के लोगों के कल्याण और प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए किशन कपूर ने बहुमूल्य योगदान दिया है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए किए गए उनके कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा।

सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मज़बूती के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाए: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ

कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभाग को अपनी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों तक निपुणता से सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल, 2024 से ई-परिवार रजिस्टर का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है और इस पहल के तहत 18.96 लाख परिवारों 99.84 प्रतिशत का पंजीकरण किया जा चुका है। पहली बार दिसंबर, 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं अब ई-परिवार पोर्टल और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में अब तक 11,016 परिवार नकल, 3,595 विवाह प्रमाण पत्र तथा 5,004 बीपीएल प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 60 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे यह 240 रुपये से बढ़कर 300 रुपये प्रतिदिन हो गई है। प्रदेश सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए टॉप-अप धनराशि के रूप में 201.51 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि हाल ही में इन समूहों को सात फूड वैन आवंटित की गई हैं और अगले वित्त वर्ष में 60 और फूड वैन उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के निर्माणाधीन सभी होटलों में स्वयं सहायता समूहों के लिए दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद जैसे साबुन आदि भी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री ने विभाग को स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों तथा प्राकृतिक खेती उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अ नलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हिम-ईरा ई-क मर्स वेबसाइट शुरू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने विभाग को सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों को लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रियता से कार्य करने को कहा।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव राजेश शर्मा, निदेशक राघव शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शिवम प्रताप सिंह, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. निपुण जिंदल तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट को असमान और अवसरवादी करार दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट असमानता को प्रदर्शित कर रहा है और बजट का एक बड़ा हिस्सा बिहार राज्य पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का और यहां की जनसंख्याओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल संशोधन करने का आहवान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश के महत्वपूर्ण मामलों जैसे बेरोजगारी, गरीबी और बढ़ती मंहगाई को संबोधित करने की दिशा में असफल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस वर्ग से संबंधित वित्तीय बाधाओं और उनसे संबंधित मुश्किलों को कम करने के लिए सेब के आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है जिससे प्रदेश के बागवानों को राहत मिलती।

सुक्खू ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट में प्रदेश में रेल विस्तार जैसे महत्वपूर्ण मामले के संबंध में भी उल्लेख नहीं है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए मजबूत रेल विस्तार आवश्यक है लेकिन इस मामले को भी नजरअंदाज किया गया है। राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की 1.5 लाख करोड़ रुपये की सीमा में बढ़ौतरी नहीं की गई है और हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए इससे संबंधित कठिन शर्ते राज्य के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को समाप्त करने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश मुश्किल वित्तीय स्थिति को झेल रहा है जिससे राज्य को प्रतिवर्ष हानि हो रही है। इस वित्तीय घाटे को कम करने के लिए और प्रदेश की राजकोषीय स्थिरता के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बजट में इस तरह के पैकेज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयकर छूट के रूप में मध्यम वर्ग को मिलने वाले लाभ में विलम्ब हुआ है क्योंकि नए प्रत्यक्ष ढांचे के लाभों का उपयोग, उपभोग और मांग को बढ़ावा देने के बजाये पिछले वर्षो में लगाए गए कर के रूप में देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह गरीब विरोधी और अवसरवादी बजट है जो भविष्योन्मुखी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ में मध्यम वर्ग के कर दाताओं के द्वारा किए जा रहे योगदान के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा इस बजट में अगले सप्ताह नए आयकर बिल का भी उल्लेख है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र में चल रही समस्याओं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य और आधुनिक कृषि पद्धति और बुनियादी ढांचे के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण को सम्बोधित करने के लिए कोई भी उपाय नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट भारत की आवश्यकताओं के अनुसार समावेशी और सहायक वित्तीय योजना बनाने में विफल रहा है। इसमें बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें और असमानताओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए कोई समाधान नहीं दिया गया है। अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश भी एक ऐसे बजट के परिणामों से जूझ रहा है जो आम लोगों की तुलना में सम्पन्न वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसा बजट बनाया जाये जो सभी नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को सही मायने में प्रतिबिम्बित करे और समाज के सभी वर्गों का समान विकास और समृद्धि सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती में किसानों के पंजीकरण के लिए फार्म लांच किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायकों की प्राथमिकता बैठक के दौरान राज्य में प्राकृतिक खेती में किसानों के पंजीकरण के लिए सरल फार्म लांच किया। किसान

ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फार्म भर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान अब इस फार्म को भरकर आसानी से प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण फार्म में किसानों की भूमि, उगाई जाने वाली फसलों, पशुओं की नस्ल और प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ अन्य विवरण होंगे। यह फार्म प्रदेश की सभी पंचायतों में किसानों को वितरित किए जाएंगे। इससे राज्य में वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1508 किसानों से 398.976 मीट्रिक टन प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, देश में मक्की पर सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रहा है। आगामी सीजन में प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं की खरीद के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। लोगों को प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की के आटे के एक किलोग्राम और पांच किलोग्राम के पैकेट 'हिम भोग' ब्रांड नाम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1054 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 1 फरवरी, 2025 तक 38.225 मीट्रिक टन मक्की के आटे की बिक्री की गई है और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की थोक इकाइयों के माध्यम से 73.52 मीट्रिक टन आटा बेचा गया है।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि आत्मा स्टाफ किसानों द्वारा भरे गए फार्म का सत्यापन करेगा। उन्होंने कहा कि फार्म को पीके3वाई पोर्टल के सीटारा-एनएफ (प्राकृतिक खेती के कृषि संसाधन विशलेषण का प्रमाणित मूल्याकंन उपकरण) से जोड़ा जाएगा।

सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना को मंजूरी

3500 मामलों के समाधान से 10 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान: मुख्यमंत्री

मुकद्दमों की संख्या कम करने और राजस्व प्राप्ति को बढ़ावा देने में कारगर होगी योजना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे इसका दायरा बढ़ाकर गैर-समाहित अधिनियमों के तहत मामलों को भी शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि डीज़ल और पेट्रोल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रित करने वाला राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम जीएसटी के दायरे से बाहर है। इस नई योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 तक के पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा। इससे गैर-समाहित अधिनियमों के तहत लंबित मामलों की संख्या को और कम किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नई योजना से लगभग 3,500 मामलों का समाधान होने की उम्मीद है। इससे लगभग 10 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

प्रदेश सरकार मुकद्दमों की संख्या को कम करने और राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत समय-समय पर विरासत मामले समाधान योजनाएं लागू की गई हैं। एक जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और लग्जरी कर जैसे राज्य करों को जीएसटी के तहत समाहित कर दिया गया था। इन करों के अंतर्गत लंबित मामलों और विवादों को सुलझाने के लिए राज्य ने अब तक तीन विरासत मामले समाधान योजनाएं शुरू की हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत 48,269 लंबित मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जिससे 452.68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और वादियों को राहत मिली है।

तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की।

तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री ने सेली एचईपी (400 मेगावाट) और मियार एचईपी (120 मेगावाट) विद्युत परियोजनाओं में रुचि व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पीएसयू/केंद्रीय पीएसयू से बीओओटी आधार पर 22 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव के जवाब में, तेलंगाना के विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है। इस दल ने विद्युत सचिव राकेश कंवर के साथ भी चर्चा की। इस टीम ने सेली और मियार जल विद्युत परियोजनाओं के स्थलों का भी दौरा किया और सिफारिश की है कि 100 मेगावाट से अधिक जल विद्युत परियोजना की क्षमता वाले स्थलों के लिए रुचि व्यक्त की जा सकती है।

प्रदेश के लिए अधिक बिजली उत्पादन और राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं तलाश करने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अंतरात्मा के मामलों में, बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है।
..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

सरकार को बताना होगा की आत्मनिर्भरता का रोड मैप क्या है

प्रदेश का कर्ज भार एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। सुक्खू सरकार ने जब दिसम्बर 2022 में सत्ता संभाली थी तब 2021-22का कर्ज भार 64000 करोड़ के करीब था। जिस गति से यह कर्ज भार बड़ रहा है उससे यह लगता है कि इसी सरकार के कार्यकाल में यह कर्ज 1. 5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जायेगा। इस वित्तीय परिदृश्य में मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं 2030 में प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का दावा कर रहे हैं। प्रदेश के वित्तीय कुप्रबंधन के लिये पूर्व की जयराम सरकार द्वारा प्रदेश की ग्रामीण जनता को मुफ्त पानी देने के लिये 125 यूनिट बिजली फ्री देने को बड़ा कारण बता रहे हैं। इसी के साथ नये संस्थान खोलने को भी एक कारण करार दे रहे हैं। यदि वित्तीय कुप्रबंधन के लिये इन मुफ्ती की योजनाओं को मुख्यमंत्री के मुताबिक एक बड़ा कारण मान लिया जाये तो यह सवाल उठता है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जो गारंटीयां प्रदेश की जनता को दी थी उन्हें किस श्रेणी में रखा जाना चाहिये। कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की हर महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह देने का वायदा किया था। हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। यदि मुफ्त पानी देने और 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने से प्रदेश का वित्तीय गणित बिगड़ गया है तो कांग्रेस के इन वायदों से क्या स्थिति हो जायेगी? मुख्यमंत्री जिस तरह का तर्क दे रहे हैं उससे सारी स्थिति संदेहास्पद हो जाती है। क्योंकि अब तो वित्त आयोग ने प्रदेश को मिलने वाली कर राजस्व घाटा राशि भी घटा दी है। इसमें 5500 करोड़ कम मिलेंगे। राज्यों की कर्ज लेने की सीमा को जो कोविड कॉल में जीडीपी का 5% कर दी गई थी अब उसे फिर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इस तरह राज्यों को कर्ज और ग्रांट दोनों में जब कमी आयेगी तो फिर राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे यह बड़ा सवाल बन जाता है। सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर लाये श्वेत पत्र में यह सब कह चुकी है। ऐसे में जब सरकार के पास संसाधन ही नहीं होंगे तब वह अपने में किसी भी वायदे को घोषणाओं के अतिरिक्त अमली जामा कैसे पहना पायेगी? अभी सरकार को सत्ता में आये दो वर्ष हुये हैं। इन दो वर्षो में अपने संसाधन बढ़ाने के लिये हर उपभोक्ता वस्तु पर शुल्क बढ़ाया है। अब पानी और बिजली जो पहले मुफ्त मिल रही थी उसकी पूरी कीमत वसूलनी शुरू कर दी है। इन सारे उपायों से सरकार ने 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है। 2024-25 में प्रदेश के कुल व्यय और आय में करीब 11000 करोड़ का घाटा रहा है। हर वर्ष करीब 10 प्रतिशत व्यय बढ़ जाता है। 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिये केवल 6270 करोड़ रखे गये हैं जो की 2023-24 के संशोधित अनुमानों से 8 प्रतिशत कम है। इस तरह जो स्थितियां बनती जा रही हैं उनके मुताबिक आने वाले समय में पूंजीगत व्यय लगातार कम होता जायेगा। क्योंकि प्रतिबद्ध व्यय में 10 से 11 प्रतिशत की वृद्धि होनी ही है। जब पूंजीगत व्यय के लिये प्रावधान कम होता जायेगा तो निश्चित रूप से सारे विकास कार्य केवल घोषणाओं तक ही सीमित रहेंगे और व्यवहार में नहीं उतर पाएंगे।

ऐसे में जब मुख्यमंत्री प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का दावा कर रहे हैं तो स्वभाविक है कि सरकार तब तक अपनी आय में इतनी वृद्धि कर लेगी कि उससे आय और व्यय बराबरी पर आ जायेंगे। लेकिन ऐसा संभव कैसे होगा। क्या इसके लिये प्रतिबद्ध खर्चो में कमी की जायेगी? सबसे ज्यादा खर्च वेतन और पैन्शन पर आता है। क्या इसके लिये आगे नियमित रोजगार में कमी की जायेगी? जिस तरह बिजली बोर्ड में युक्तिकरण के नाम पर कर्मचारियों के पदों में कटौती की जा रही है वैसा ही सारी सरकार में होगा। इस समय कर्मचारियों के बकाये के रूप में करीब 9000 करोड़ की देनदारी है। क्या इस सबके लिये आम आदमी पर करों और शुल्क का भार बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई साधन संभव है? क्या सारा कुछ प्राइवेट सैक्टर के हवाले करने की योजना बनाई जा रही है? क्योंकि सरकार में मंत्रियों और दूसरे राजनीतिक पदों पर हो रहे खर्चो में तो कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में आम आदमी ही बचता है जिसे किसी भी नाम पर ठगा जा सकता है? जब मुफ्ती की हर घोषणा वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देती है तो फिर कांग्रेस भी हर चुनाव के लिये ऐसी घोषणाएं क्यों करती हैं। क्या मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार हाईकमान के सामने अपने तर्क नहीं रख पाते हैं? क्या आने वाले बजट में सरकार यह इमानदारी बरतने का साहस करेगी कि जो कुछ भी करों और शुल्कों में बढ़ौतरी की जानी है इसकी घोषणा बजट के रिकॉर्ड पर आयेगी या फिर आम आदमी को ठगने के लिए फिर कर मुक्त बजट देने की प्रथा निभाई जायेगी। यह बजट सरकार और पूरी पार्टी की ईमानदारी का एक दस्तावेज बनेगा यह तय है। क्योंकि अब सरकार की कथनी और करनी पर सीधे सवाल उठने का समय आ गया है। सरकार को बताना होगा कि उसका प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप क्या है?

केन्द्रीय बजट 2025-26 की मुख्य बातें

भाग – ए

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

बजट अनुमान 2025-26

उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4. 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।

विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम

राज्यों की भागीदारी से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण

राज्यों की भागीदारी से 'ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण' नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा ताकि कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता

सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6-वर्षीय 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' प्रारम्भ करेगी।

केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षो के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

बिहार में मखाना बोर्ड

मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।

मत्स्य उद्योग

सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी।

कपास उत्पादकता मिशन

कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी।

असम में यूरिया संयंत्र

नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई

एमएसएमई के वर्गीकरण मानदण्ड में संशोधन

सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमश: 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्टार्ट-अप के लिए निधियों का कोष

विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।

पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना

5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षो के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा।

फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम

भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा।

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय

भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता

बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापना की जाएगी।

विनिर्माण मिशन – 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाना

'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।

विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश

I. लोगों में निवेश

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदण्डों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

अगले 5 वर्षो में सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी

भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम

स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा।

राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र

'मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड' विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

आईआईटी में क्षमता का विस्तार

6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुगम बनाने के लिए वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा।

शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र

500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षो में 75000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।

सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र

सरकार अगले 3 वर्षो में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण

शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक -आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा।

पीएम स्वनिधि

इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डो और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

सरकार गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी।

II. अर्थव्यवस्था में निवेश

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी

सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता

सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ लाख करोड़ रूपए के आवंटन का प्रस्ताव।

परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30

घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025-30 के लिए दूसरी योजना।

जल जीवन मिशन

बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया।

शहरी चुनौती कोष

एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा जिसे

शेष पृष्ठ 5 पर.....

केन्द्रीय बजट 2025–26 की मुख्य बातें

.....पृष्ठ 4 का शेष

2025 – 26 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहर शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।

20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉडयूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव।

पोत निर्माण

पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा।

निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचनासुसंगत मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।

समुद्री विकास कोष

25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49 प्रतिशत होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा।

उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम

अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने – ले – जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा।

पर्वतीय आकांक्षी और उत्तर – पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी समर्थन दिया जाएगा।

बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा।

मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

बिहार में पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

खनन क्षेत्र सुधार

टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी।

स्वामिह फंड टू

सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाईयों को पूरा करने के कार्य में तेजी करने के उद्देश्य से 15 हजार करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा।

रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन

चुनौती मोड के जरिये राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।

III. नवाचार में निवेश

अनुसंधान, विकास और नवाचार

पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

डीपटैक फंड ऑफ फंड्स

अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए डीप टेक फंड अ फ फंड्स की संभावना तलाशी जाएगी।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप

बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएस में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10 हजार फैलोशिप।

फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइंस के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।

नेशनल जियो स्पेटियल मिशन

बुनियादी जियो स्पेटियल अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए नेशनल जियो स्पेटियल मिशन की घोषणा।

ज्ञान भारतम मिशन

शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपी विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी।

विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात

निर्यात संवर्द्धन मिशन

वाणिज्य मंत्रालय एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्द्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। इसके तहत अलग – अलग क्षेत्रों और मंत्रलयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे।

भारत ट्रेडनेट

व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) स्थापित किया जाएगा।

जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

ऊभरते टियर – 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी।

फ्यूल के रूप में सुधार : वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास

बीमा क्षेत्र में एफडीआई

भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।

एनएबीएफआईडी द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा

एनएबीएफआईडी अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉड के उद्देश्य से आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगा।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ''ग्रामीण क्रेडिट स्कोर'' फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।

पेंशन क्षेत्र

पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना का प्रस्ताव।

विनियामक सुधार हेतु उच्चस्तरीय समिति

सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी नियमों, प्रमाण लाइसेंस और अनुमति की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव।

राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक

प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा।

जन विश्वास विधेयक 2.0

जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव।

खंड बी

प्रत्यक्ष कर

नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा।

वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी।

यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, वचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धन राशि उपलब्ध होगी।

नया आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों दोनों की दृष्टि से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी।

प्रत्यक्ष करों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का परित्याग होगा।

संशोधित कर संरचना

नई कर व्यवस्था में संशोधित कर संरचना निम्नानुसार होगी।

0 – 4 लाख रुपए	शून्य
4 – 8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8 – 12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12 – 16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16 – 20 लाख रुपए	20 प्रतिशत
20 – 24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

टीडीएस/टीसीएस को तर्क संगत बनाना

टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम कर उसे तर्क संगत बनाना

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दो गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है।

किराये पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये की गई।

भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण स्कीम (एलआरएस) के अंतर्गत धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।

उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर – पैन मामलों पर ही लागू होंगे।

विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीसीएस के भुगतान में विलंब को गैर – आपराधिक घोषित करने का प्रावधान।

अनुपालन बोझ को कम करना

छोटे धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया गया।

कर दाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी दो संपत्तियों के लाभ की अनुमति का प्रस्ताव।

व्यवसाय करने की सुगमता

तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतराष्ट्रीय लेन – देन के मामलों में आर्म्स लेन्थ मूल्य निर्धारण करते हेतु एक योजना की शुरुआत।

अंतरराष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने तथा निश्चितता को बनाए रखने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार।

29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम (एनएसएस) से किए गए आहरण पर छूट।

एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव जो समग्र सीमाओं के अधीन सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है।

रोजगार एवं निवेश

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण स्कीमों के लिए निश्चिचता

उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव जो ऐसी निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है।

विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों की आपूर्ति के लिए उपकरण घटकों को स्टोर करने वाले अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए सुरक्षित बंदरगाह सेवा आरंभ की गई है।

अन्तर्देशीय जहाजों के लिए टन भार योजना

देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्टार्ट – अप के निगमन का विस्तार

1.4.2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्ट – अप इको – सिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार कर स्टार्ट – अप लाभ प्रदान किए गए हैं।

वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ)

श्रेणी – 1 और श्रेणी – 2 एआईएफ अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

सॉवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश तिथि का विस्तार

सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31, मार्च, 2030 तक करने का प्रस्ताव है।

अप्रत्यक्ष कर

औद्योगिक वस्तुओं के सीमा शुल्क ढांचे का युक्तिकरण

केंद्रीय बजट 2025 – 26 के प्रस्तावों में

7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। यह 2023 – 24 के बजट में हटाई गई सात टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद, शेष बची टैरिफ दरें 'शून्य' दर सहित आठ रह जाएंगी।

मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों, जहां ऐसा दायित्व मामूली रूप से कम होगा, को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव है।

एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार न लगाने का प्रस्ताव है। उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी।

अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपये के राजस्व का परित्याग होगा

औषधि/दवाओं के आयात पर राहत

36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट

6 जीवन रक्षक दवाएं 5 प्रतिशत के रियायती सीमा – शुल्क्क दवाओं में शामिल औषध कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त। 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ ही 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव

घरेलू विनिर्माण और मूल्य्य वर्धन को सहायता

महत्वपूर्ण खनिज

कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैट्री के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट

वस्त्र

घरेलू तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा

दो अन्य प्रकार के शटल – रहित करघों वाली टेक्सटाइल मशीनरी सीमा शुल्क से मुक्त

बुने हुए वस्त्रों पर 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20 प्रतिशत अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

इन्टेरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया

ओपेन सेल्स और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

ओपेन सेल्स के अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट

लिथियम आयन बैट्री

इलेक्ट्रिक वाहनों के बैट्री के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैट्री विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट

पोत परिवहन क्षेत्र

पोत निर्माण में कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जो पर अगले दस वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट

पुराने पोतों के लिए भी ऐसी ही छूट

दूरसंचार

कैरियर ग्रेड इथरनेट स्वीच पर बुनियादी सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर लाया गया

निर्यात संवर्धन

हस्तशिल्प वस्तुएं

हस्तशिल्प की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई, आवश्यकता पड़ने पर आगे तीन महीनों के लिए और बढ़ाई जा सकती है

शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में नौ और वस्तुएं शामिल की गई

चमड़े की वस्तुएं

वेट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट

क्रश लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क से छूट

समुद्री उत्पाद

फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) और ऐसे ही उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलीसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

रेल वस्तुओं के लिए घरेलू एमआरओ में वायुयानों और जलपोतों के मरम्मत के लिए आयातित एमआरओ के समान ही छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा

ऐसी वस्तुओं के निर्यात की समय – सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई जिसे आगे एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है

व्यापार सुविधा

प्रोविजनल कर निर्धारण की समय – सीमा

व्यवसाय प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय – सीमा तय करने का प्रस्ताव जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है

स्वैच्छिक अनुपालन

आयातक या निर्यातक की सुविधा के लिए माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकते हैं और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं अंतिम उपयोग की समय – सीमा बढ़ाई गई

आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय – सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई

ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा

प्रदेश के लिए नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपये की 127 परियोजनाएं स्वीकृतः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, कुल्लू तथा किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपये की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं, इनमें से 412.75 करोड़ रुपये की 50 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग तथा 179.07 करोड़ रुपये की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं।

उन्होंने कहा कि इन स्वीकृत परियोजनाओं में दो राज्य प्राथमिकताएं कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.5 एलएलपीडी क्षमता के डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र तथा 96 ईलैक्ट्रिक बस चार्जिंग प्वाईंट की स्थापना भी शामिल है। मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि आरआईडीएफ के तहत

1087.77 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.28 प्रतिशत अधिक है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ वर्तमान सरकार प्रदेश की आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, पर्यटन, आधारभूत ढांचा, कृषि, बागवानी, उद्योग तथा महिला सशक्तिकरण व बाल विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सभी क्षेत्रो एवं समाज के सभी वर्गो के त्वरित, संतुलित, समावेशी एवं सत्त विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी को 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले तीन वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं लेकर आएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ टी-टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के टी-टूरिज्म म डल का भी अध्ययन किया जाएगा। राज्य सरकार नशा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी।

बैठक में कांगड़ा जिले के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में एक और अनाज मंडी बनाने की मांग की और कहा कि क्षेत्र में बहुत से किसान गन्ना की खेती से जुड़े हैं और राज्य सरकार की ओर से इन्सेंटिव मिलना चाहिए।

देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा क्षेत्र में खुले नए कार्यालय में स्टाफ की नियुक्ति की जाए और लोगों की सुविधा के लिए नए पटवार सर्किल खोले जाएं। उन्होंने स्कूल और कॉलेजों में खेल के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की।

ज्वालामुखी क्षेत्र के विधायक संजय रतन ने कहा कि पिछली बैठक के 60 प्रतिशत कार्य पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम जारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि 8 फरवरी, 2024 को क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान उन्होंने 14 घोषणाएं की थी और 12 पूरी हो चुकी है। उन्होंने ज्वालामुखी में पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ खुंडियां में दमकल विभाग की चौकी खोलने की मांग की।

पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने पालमपुर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 70 करोड़ रुपये तथा 135 करोड़ रुपये की सीवरेज स्कीम के साथ-साथ हेलीपोर्ट निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रों टी-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और न्यूगल पुल की मरम्मत करवाई जाए। उन्होंने पालमपुर में वेटनरी यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की।

बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम बैजनाथ में आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीड़-बिलिंग का पूरे विश्व में पैराग्लाइडिंग के लिए विशेष स्थान है इसलिए यहां पर पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाए। उन्होंने बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के लिए बैजनाथ से हैलीटैक्सी शुरू करने की भी मांग की।

मनाली क्षेत्र से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने अपने चुनाव क्षेत्र में आईस स्केटिंग रिंक का निर्माण कार्य तेज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि निर्माणधीन सड़क पर भी एनएचएआई टोल टैक्स वसूल कर रही है, जो गलत है। सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। उन्होंने पतलीकूहल में एचपीएमसी के कोल्ड स्टोर को सीए स्टोर में अपग्रेड करने और दो रोपवे के निर्माण में तेजी लाने की मांग की।

कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू के लिए निरंतर एयर कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि चंडीगढ़ से भुंतर के लिए सीधी हवाई सेवा की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए पर्याप्त स्टाफ की मांग की।

बैठक में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष तथा संबंधित उपायुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विधायक प्राथमिकता की डीपीआर तैयार करने में फोरेस्ट क्लीरेंयस व गिफ्ट डीड औपचारिकताओं को अधिमान दे :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के दूसरे सत्र की

अध्यक्षता की। सत्र के दौरान जिला सोलन, चंबा, बिलासपुर तथा लाहौल स्पीति के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है तथा राज्य सरकार गांव के लोगों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। व्यवस्था में बेहतरी के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कर्ज की दलदल से बाहर निकालने के लिए हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनना होगा, जिसके लिए नए सुझावों का स्वागत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश का ऐसा पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गाय का दूध 45 रूपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की को 30 रुपये तथा गेहूं 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिमभोग आटा भी बाजार में उतारा है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाईट आरम्भ की है ताकि उनकी आर्थिकी को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' के रूप में अपनाया है तथा इन बच्चों को एक्पोजर विजिट पर भी भेजा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जा रहा है तथा इसी के दृष्टिगत सभी प्राथमिकताओं को पुनः अधिमान दिया गया है तथा बिना किसी भेदभाव के नाबार्ड को संस्तुति की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे विधानसभा क्षेत्रों सहित अन्य चुनाव क्षेत्रों में भी पिछले दो वर्ष में 251 योजनाओं के लिए 1691 करोड़ रुपये नाबार्ड द्वारा स्वीकृत करवाए गए हैं।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायक प्राथमिकता की डीपीआर तैयार करते समय फोरेस्ट क्लीरेंयस तथा गिफ्ट डीड आदि औपचारिकताओं को पूर्ण करने में अधिमान दें ताकि परियोजनाओं का कार्य समय पर आरम्भ किया जा सके। उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं को पूर्ण करने में कोताही बरतने पर अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी ने उनके चुनाव क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में रोपवे निर्माण करने की मांग की।

नालागढ़ क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह बावा ने पिंजौर-बद्दी तथा बद्दी-नालागढ़ सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में नशा माफिया और अवैध खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी की सुविधा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने की मांग की। उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया।

कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने उनके चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जाति बहुल गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने धर्मपुर में बस स्टैंड बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुविधा को सुदृढ़ करने व कौशल्या बांध बनाने की मांग की।

चंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज नैयर ने मुख्यमंत्री का चंबा मेडिकल कॉलेज को 170 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने, चंबा में इंडोर स्टेडियम, बस अड्डा तथा मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने हेलीपोर्ट के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की मांग की।

लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनुराधा राणा ने विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की मांग करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सीबक थोर्न को जीआई टैग दिलवाने की मांग की, ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती भूस्खलन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी चर्चा में भाग लिया और अपने सुझाव सरकार को दिए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, संबंधित उपायुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय बजट में हिमाचल के लिए आर्थिक मदद मांगे जयरामःअवस्थी

शिमला/शैल। विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाना छोड़कर, इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में हिमाचली हितों की पैरवी करें। एक प्रेस विज्ञप्ति में अवस्थी ने कहा कि जयराम ठाकुर मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए रोज नया तथ्यहीन बयान जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे हिमाचल और हिमाचल के लोगों के हितों के प्रति इतने ही संवेदनशील हैं तो उन्हें केन्द्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक मदद की मांग करनी चाहिए।

अवस्थी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष, 2023 में आई आपदा के 10,000 करोड़ रुपये भी अभी तक जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के एनपीएस में लगभग 9000 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के पास पड़े हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार से यह पैसा हिमाचल प्रदेश को दिलवाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं।

संजय अवस्थी ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की फिजूलखर्ची के कारण प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ा। इसी कारण पिछली भाजपा सरकार ने वर्तमान सरकार को 75,000 करोड़ रुपये का ऋण और कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में 10,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ विरासत में छोड़ा। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में जितना भी ऋण लिया है उसका 63 प्रतिशत हिस्सा पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण के मूलधन और उसके ब्याज को चुकाने के लिए खर्च करना पड़ रहा है।

विधायक ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य के संसाधनों में बढ़ौतरी करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए, जबकि पूरे पांच साल तक डबल इंजन की सरकार का नारा दिया जाता रहा। हकीकत यह है कि डबल इंजन की सरकार के कारण हिमाचल प्रदेश डबल स्पीड से कर्ज के दलदल में फंसता चला गया और जयराम सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

मुख्यमंत्री ने एचपीएएस अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पीटरहॉफ शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक

सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन ''अभिव्यक्ति'' की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा एचपीएएस को और सशक्त करेगी। उन्होंने अधिकारियों से सरकार के निर्णयों में भरपूर सहयोग और योगदान देने का आहवान करते हुए कहा कि अधिकारी सरकार की ताकत हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की चुनौतियों का सामना नई तकनीक और नई सोच के साथ ही किया जा सकता है। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ निरंतर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 'डिले करप्शन' को शून्य करने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न प्रक्रियाओं और नियमों में सकारात्मक सोच के साथ सार्थक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य और 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गठन के बाद आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक चुनौतियों का मजबूती से सामना किया। दृढ़ इरादों और दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप वर्तमान में हिमाचल हर क्षेत्र में सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, जल विद्युत, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा स्टोरेज और कृषि व बागवानी पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि वह दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी सराहनीय सेवाएं प्रदान कर अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार भी कर्मचारियों व अधिकारियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एचपीएएस अधिकारियों की मांगों पर सहानुभूतिर्पूक विचार करेगी और इसके लिए शीघ्र ही उच्च स्तरीय बैठक में विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एचपीएएस अधिकारी संघ के नए लोगो, फ्लैग और स्मारिका का विमोचन भी किया।

एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रवण मांटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों और मांगों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर एचपीएएस अधिकारी संघ के सभी सदस्यों ने विद्युत सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया तथा इस संबंध में फार्म भरकर प्रस्तुत किए।

एसोसिएशन महासचिव प्रशांत सरकैक ने आभार प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर विधायक नीरज नैयर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल चंद, एसोसिएशन के विभिन्न पदाधिकारी, सेवानिवृत एचपीएएस अधिकारी और गणमान्य उपस्थित थे।

उप-मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में किया स्नान

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने महाकुंभ मेला-2025 में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया। इस अवसर

पर उनके साथ बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री भी उपस्थित रहीं।

उप-मुख्यमंत्री ने संगम में श्रद्धापूर्ण डुबकी लगाते हुए देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का संगम स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का प्रतीक है, जहां आकर मन को अद्भुत शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है।

इस अवसर पर अग्निहोत्री ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और समाज में सद्भावना का संचार करता है। स्नान के उपरांत उप-मुख्यमंत्री ने संगम क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण किया और स्थानीय श्रद्धालुओं से संवाद किया।

हिमुडा पर्यटन आधारित परियोजनाओं के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करें :धर्माणी

शिमला/शैल। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान महत्त्वाकांक्षी माउंटेन सिटी परियोजना की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि शिमला के निकट जाठियादेवी में निर्मित होने वाली माउंटेन सिटी परियोजना शिमला की भीड़भाड़ को

कम करने की दिशा में सहायक साबित होगी। यह परियोजना आधुनिक शहर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सतत् विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिमला के विकास नगर में अत्याधुनिक व्यावसायिक परिसर का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए विषय विशेषज्ञ सलाहकार की सेवाएं ली जाएगी। प्रदेश की पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना में कुशल नियोजन को सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने हिमुडा की परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमुडा को पर्यटन आधारित परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसके दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूमि की खरीद संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जिला कांगड़ा के नरघोटा में प्रस्तावित पर्यटन गांव परियोजना की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला कांगड़ा की ज्वालामुखी तहसील में मौहल भाटी में 125 कनाल भूमि की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिमुडा को औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजनाओं के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहिए। हिमुडा को परियोजनाओं के मार्केटिंग के लिए भी कार्य करना चाहिए। बैठक में एग्रीगेटर्ज और रेरा से प्राधिकृत रियल स्टेट एजेंटों की सेवाएं लेने के लिए विचार विमर्श किया गया।

बैठक में हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, प्रधान सचिव आवास देवेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुडा संदीप कुमार, गैर सरकारी सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के कॉमन कैडर से सुनिश्चित होगी बेहतर चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और सुपरस्पेशिएलिटी संस्थानों में भविष्य की सभी संकाय नियुक्तियों के लिए एक कॉमन कैडर स्थापित करने का सैद्धांतिक रुप से निर्णय लिया है। इस व्यवस्था से समान, दक्ष, बेहतर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी।। वर्तमान में कॉलेज-विशिष्ट कैडर प्रणाली के अनुसार संकाय नियुक्तियां की जाती हैं, जिससे प्रशासनिक असमानता, सेवा शर्तो में असंगता और विशेष रूप से नव स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों में संकाय की कमी को देखा गया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कॉमन कैडर प्रणाली के माध्यम से संकाय की भर्ती के लिए एक समान प्रणाली, करियर प्रगति और अंतर-संस्थागत स्थानांतरण के लिए एकीकृत संरचना स्थापित की जाएगी, जिससे संकाय प्रबंधन के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढांचा सुनिश्चित होगा। इस पहल से सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सेवा शर्तो में सामंजस्य स्थापित करते हुए भर्ती प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और करियर उन्नति के अवसरों के लिए मानक स्थापित होंगे। इससे संकाय के बेहतर उपयोग और संसाधनों को आवश्यकतानुसार कुशलतापूर्वक आवंटित करने में भी मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य करियर विकास में असमानताओं को दूर करके संकाय पदोन्नति के लिए योग्यता आधारित प्रणाली को बढ़ावा देकर चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ेगी, संस्थानों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्रीं ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कॉमन कैडर की स्थापना से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च मानक स्थापित होंगे और राज्य के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित होगी।

लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है तथा इसके निर्माण का पूरा खर्च केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिए। इसके साथ ही भानुपल्ली-बैरी और चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईन को बिछाने का पूरा खर्च भी केन्द्र सरकार को उठाना चाहिए।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन-परवाणु फोरलेन की स्थिति सबसे दयनीय है क्योंकि इसकी डिजाइनिंग सही ढंग से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में उनकी चर्चा केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से हुई है और उन्होंने इस फोरलेन की रि-डिजाइनिंग और रि-एलाइनमेंट करने की मांग की है।

एक अन्य प्रश्न के जवाब में ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश है जिसकी आबादी लगभग 70 लाख है इसलिए 153 आईएएस अधिकारी रखना उचित नहीं है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नए काडर में नए आईएएस और आईपीएस अधिकारी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 115 आईएफएस अधिकारियों को भी कम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, इसलिए सभी विभागों में सकारात्मक बदलाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक दखलअंदाजी को कम करके लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है।

इससे पहले, ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू, डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक विनोद सुल्तानपुरी, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरुण शर्मा, प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम निदेशक मण्डल के सदस्य जतिन साहनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश ठाकुर व सुरेन्द्र सेठी, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उप-मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री किशन कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मंत्री किशन कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किशन कपूर ने अपने राजनीतिक जीवन में कड़े संघर्ष किए और सदैव उच्च आदर्शों पालन किया। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि किशन कपूर द्वारा लोगों के कल्याण और प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा।

उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

आज की परिस्थितियों में भाजपा भी बराबर सवालों के घेरे में आती है

- महत्वपूर्ण सवालों पर भाजपा की चुप्पी सन्देह के घेरे में
- पत्रकारों को भी सरकार का प्रवक्ता या आम आदमी का पक्षकार दोनों में से एक चुनना होगा

शिमला/शैल। इस समय हिमाचल में जिस तरह का राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियां बनती जा रही हैं उनके परिदृश्य में सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दल भाजपा भी बराबर सवालों के घेरे में आती जा रही है। यह बराबर आरोप लगता जा रहा है कि वर्तमान सुक्खू सरकार तभी तक सत्ता में बनी रहेगी जब तक उसे परदे के पीछे से भाजपा का सहयोग हासिल है। यह स्थितियां क्या है और कैसे निर्मित हुई तथा इसका प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर खुलकर चर्चा करना व सवाल उठाना आवश्यक हो गया है। सुक्खू सरकार ने दिसम्बर 2022 में सत्ता संभाली और फिर पहला काम प्रदेश को यह चेतावनी देने का किया कि राज्य के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। इस चेतावनी के बाद विधायकों के शपथ ग्रहण से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी। इस मान्यता का प्रभाव यह हुआ कि इस सरकार द्वारा पिछली सरकार के अंतिम छः माह में लिये फसलों को पलटने के कारण पहले बीस दिनों में ही जो रोष का वातावरण उभरा था उसको ठण्डे बस्ते में डालने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका डालने का रूट ले लिया गया और पूरा मामला वहीं रूक कर रह गया। इसी के साथ सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का सूत्र पकड़कर प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही को अपने- अपने पदों पर सुरक्षित रखते हुये भ्रष्टाचार के खिलाफ रस्म अदायगी का शिष्टाचार भी नहीं निभाया। इसका परिणाम हुआ कि भ्रष्टाचार तो अपनी जगह फलता फूलता रहा और उसके आरोप पत्र बम्बों की शक्ल में सार्वजनिक भी हुये। इन पत्र बम्बों के सार्वजनिक होने पर मीडिया के खिलाफ तो मामले दर्ज हो गये लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ब्यानों/ प्रतिब्यानों की औपचारिकता से आगे नहीं बढ़े। आज तक दोनों पक्ष इस धर्म की अनुपालना पूरी ईमानदारी से निभाते आ रहे हैं। 2017 में जब सुक्खू के चुनाव शपथ पत्र को बसन्त सिंह ठाकुर ने चुनौती दी और मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक पहुंचा और उच्च न्यायालय ने इसकी जांच के आदेश दिये तब हमीरपुर भाजपा के सारे शीर्ष नेतृत्व ने इस पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर उस समय तो अपना धर्म निभा दिया। लेकिन उसके बाद आज तक भाजपा इस सबसे संवेदनशील मुद्दे पर मौन साधकर बैठ गयी है। इसी मौन का परिणाम है कि मुख्यमंत्री को सदन में यह कहने का साहस हुआ कि ई.डी. की हिरासत में पहुंचे ज्ञानचन्द विधानसभा में मेरा समर्थक है तो लोकसभा में अनुराग ठाकुर का समर्थक है। स्मरणीय है कि 2017 में मुख्यमंत्री के जिस जमीन मुद्दे को हमीरपुर के भाजपा विधायकों और दूसरे पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से उठाया था आज उस मुद्दे पर यह लोग चुप हो गये हैं। जबकि पिछले वर्ष हमीरपुर और नादौन में ई.डी. तथा आयकर की छापेमारी से पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। कुछ लोग ई.डी. की हिरासत में पहुंच गये हैं। इसी प्रकरण का शिकायतकर्ता युद्ध चन्द बैंस खुलकर सामने आ गया है। यह प्रकरण प्रदेश की राजनीति का केन्द्र बिंदु बन चुका है। लेकिन इसी केन्द्रीय मुद्दे पर भाजपा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है।

मुख्यमंत्री के व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र ने प्रदेश को कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में लाकर खड़ा कर दिया है जिससे आने वाला भविष्य भी प्रश्निंत होता जा रहा है। जिस तरह से हर सेवा और उपभोक्ता वस्तु के शुल्क बढ़ाये जा रहे हैं। उसी अनुपात में प्रदेश के आम आदमी की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है। बिजली राज्य का तमगा लेकर उद्योगों को बुलाने वाले राज्य में आज प्रदेश का आम उपभोक्ता बिजली के बिल अदा करने में असमर्थता के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन विपक्ष यह सवाल नहीं उठा पा रहा है कि आम आदमी पर इतना कर्जभार लादने के बाद भी सरकार का कर्ज लेना कम नहीं हो रहा है। यह कर्ज कहां निवेशित हो रहा है इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है। जो अधिकारी पिछली सरकार में सर्वे सर्वा और उन्ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके खिलाफ सदन में आरोप लगाये थे। आज वही अधिकारी इस सरकार में मुख्य सलाहकार की भूमिका में है। यह आम चर्चा है कि ऐसे ही अधिकारी वर्तमान और पूर्व सरकार में सबसे बड़े संपर्क सूत्र की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिये सारा विरोध रस्म अदायगी की भूमिका से आगे नहीं बढ़ रहा है। एक ओर भाजपा सांसद हर्ष महाजन दावा कर रहे हैं कि जब चाहे तब सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन सरकार से तीखे सवाल पूछने का साहस नहीं कर रहे हैं। इस समय प्रदेश बेरोजगारी में देश में छठे स्थान पर पहुंच चुका है। आठ लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। इस स्थिति में जिस तरह से विधानसभा में हुई नियुक्तियों का पूरा प्रकरण सारे दस्तावेजी परमाणों के साथ सामने आया है और उस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया विधानसभा सचिवालय की ओर से सामने आयी है उससे एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है। इस पर विपक्ष किस तरह से आगे बढ़ता है यह देखना रोचक होगा। क्योंकि यह एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आठ लाख बेरोजगारों का भविष्य और विश्वास टिका हुआ है।

इस परिदृश्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर ब्यानबाजी के रश्मि विरोध से हटकर किसी जनआन्दोलन का रास्ता सरकार के प्रवक्ता होने की भूमिका छोड़कर आम आदमी के पक्ष में सरकार से तीखे सवाल पूछने का साहस दिखा पाते हैं या नहीं। इस सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से सरकार ने मानहानि का रूट छोड़कर सीधे अपराधिक मामले दर्ज करने की नीति अपनायी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उससे पूछे जाने वाले तीखे सवालों से डरने लगी है। पत्रकारों को अपने बेवाक लेखन से आगे बढ़ना होगा। पत्रकारों में इस तरह के वर्ग भेद पैदा करके कोई भी सरकार ज्यादा समय तक अपने ऊपर ईमानदारी का चोला पहन कर जनता को गुमराह नहीं कर सकती। इस तरह कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन गयी है उनमें सत्ता पक्ष तो कटघरे में आता ही है लेकिन विपक्ष भी अपनी तटस्थता के कारण बराबर सवालों में आता है।

क्या कांग्रेस में एक

.....पृष्ठ 1 का शेष

अपनाता है या नहीं। यही स्थिति इस समय प्रदेश के मीडिया की है क्योंकि आज सरकार ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लकीर खींचकर सचिवालय में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया है उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या पत्रकार की अनदेखी की तब पार्टी के छः विधायक टूटकर भाजपा में चले गये। यह नेतृत्व के खिलाफ पहला मुखर रोष था। इस रोष के बाद तो प्रदेश सरकार के कुछ फैसले ऐसे राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने की हरियाणा और महाराष्ट्र विधान सभाओं के चुनाव में भी मुद्दा बने। अब दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस को कोई बड़ी सफलता मिलने का आसार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की विश्वसनीयता उसकी राज्य सरकारों के फैसलों और कार्यशैली से बनेगी। जो सरकार पहले दिन से ही मीडिया को बांटने और दबाने की नीति पर चलते-चलते दो साल से मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त में भेद करके सचिवालय में प्रवेश देने के लिये यह सूची जारी करने पर आ जाये उसकी मानसिकता का अनुमान कोई भी लगा सकता है। शायद इसी सबको देखते हुये हर्ष महाजन जैसे भाजपा नेता को यह दावा करने का साहस हुआ है कि हम जब चाहें तब सरकार गिरा सकते हैं। शायद इसी सब को देखते हुये कांग्रेस के दो दर्जन विधायकों ने अपना रोष हाईकमान के सामने रखने के लिये हस्ताक्षर नीति का सहारा लिया है।

कांग्रेस के विधायकों ने कहा

.....पृष्ठ 1 का शेष

तो कांग्रेस के ही बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो हम से संपर्क कर रहे हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसी ही है जैसी स्थिति आपकी है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मुख्यमंत्री विपक्ष में हुआ करते थे तो विधायक इंस्टिटयूशन की बहुत लंबी-लंबी बातें करते थे कि विधायकों के लिए यह होना चाहिये । विधायकों की प्रेरोगेटिव के लिए हमको एक मंच पर सारी चीजों को छोड़ कर के काम करना चाहिए, लेकिन आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हैं विधायक इंस्टिटयूशन को पूरी तरह से बर्बाद किया है वह वर्तमान की सरकार के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि हम विधायक चुने हुए हैं लेकिन विधायक होकर के भी हम डिप्टी कमिशनर को लिखते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की इस स्कीम के लिए आप पैसा स्वीकृत करिये लेकिन हमारे कहने पर पैसा स्वीकृत होता नहीं है।

हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग कहीं चुनाव में नहीं जीते हैं, जिन्होंने कही से चुनाव भी नहीं लड़ा है, अगर चुनाव लड़ा है तो चुनाव हारे हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी में एक एक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन चार-चार नेता है। जिसके नाम सुक्खू ने डिप्टी कमिशनर को सचिवालय से भेजे है, कि विधानसभा क्षेत्र में इन नेताओं के कहने पर काम होंगे बाकियों के कहने पर काम नहीं होंगे। उस प्रकार से पैसा स्वीकृत किया जा रहा है, एक तरह से विधायकों को अपमानित करने का यह क्रम जो है लगातार चला हुआ है और हम इस बात को लेकर के हैरान होते हैं कांग्रेस के वह लोग जो किसी सरकारी दायित्व पर नहीं लेकिन अधिकारियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। इन नेताओं को अधिकारियों के कार्यक्रम में बुलाया जा रहा हैं, टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शन में वह वहां पर जाकर के भाषण दे रहे हैं और इनके मंत्री जहां प्रवास पर जाते हैं स्थानीय विधायक को निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के विधायकों को निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व.वीरभद्र सिंह, प्रो. प्रेम कुमार धूमल भी विधायकों को उचित स्थान एवं मंच देते थे।